INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य परीक्षा हेतु

HANDWRITTEN NOTES

[भाग -3]

भारत + विश्व + राजस्थान की अर्थव्यवस्था

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 3

भारत + विश्व + राजस्थान की अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RAS (Rajasthan Administrative Service) (मुख्य परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams**" **मुख्य** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें/*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp करें - https://wa.link/9qwi7z

Online order करें - https://bit.ly/4lwfqPD

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम**

क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय • प्रकार • शाखाएं • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	1-4
2.	कृषि • भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियां • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र • खाद्य प्रबंधन • नवीनतम कृषिगत सुधार और चुनौतियाँ • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	5-31
3.	औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां • औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त • उदारीकरण • वैश्वीकरण • निजीकरण • आर्थिक सुधार • अवसरंचना और आर्थिक वृद्धि	31-54
4.	मुद्रास्फीति – कीमतें और मांग / पूर्ति प्रबंधन • अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र • WPI, CPI	55-67

	• मुद्रास्फीति पर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव • कीमतें, मांग और पूर्ति प्रबंधन • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
5.	केंद्र- राज्य वित्तीय संबंध • नवीनतम वित्त आयोग • राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम • राजकोषीय सुधार • राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	67-76
6.	बजटीय प्रवृत्तियां और राजकोषीय नीति • बजट निर्माण एवं इसके प्रकार • बजट 2023-24 • राजस्व और व्यय प्रवृत्तिया • वस्तु एवं सेवा कर • मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न	76-98
7.	आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका • नीति आयोग • पंचवर्षीय योजनायें • आर्थिक समस्यांए एवं सरकार की पहलें	99-110
8.	सामाजिक क्षेत्र • गरीबी • बेरोजगारी	111-128

	• असामनता • स्वास्थ्य सेवा • नई शिक्षा नीति	
	वैश्विक अर्थव्यवस्था	
1.	वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां • विश्व बैंक • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) • विश्व व्यापार संगठन • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	129-139
2.	सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	139-143
	राजस्थान की अर्थव्यवस्था	
1.	कृषि परिदृश्य • उत्पादन एवं उत्पादकता • जल संसाधन और सिंचाई • कृषि विपणन • डेयरी और पशुपालन • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	144-152
2.	ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना • पंचायती राज • राज्य वित्त आयोग • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	152-162

3.	औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा • औद्योगिक वृद्धि और नवप्रव्रत्तियां • पंचवर्षीय योजनायें • खादी और ग्रामोद्योग • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	163-178
4.	अवसंरचना विकास • विद्युत और परिवहन • निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता परियोजना	178-184
5.	प्रमुख विकास एवं आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं • प्रमुख योजनायें • राजस्थान का बजट 2023-24 • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	184-205
6.	बुनियादी सामाजिक सेवाएं • शिक्षा व स्वास्थ्य • गरीबी एवं बेरोजगारी • सतत विकास लक्ष्य • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	205-227
7.	राज्य आर्थिक समीक्षा 2023-24	228-247

अध्याय – 2
कृषि

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार हैं । एक ओर जहाँ यह भारत की अधिकांश जनसंख्या को प्रभावित करती हैं, वही दूसरी ओर यह भारतीय जलवायु (Indian Climate), मृदा एवं अन्य संस्थागत कारकों से भी प्रभावित होती हैं ।

भारत एक कृषि प्रधान देश हैं । अभी भी यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण कृषि पर निर्भर हैं । यद्यपि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का अंशदान वर्ष 1951 में 60% से घटकर वर्ष 2014-15 में 14.7% तक पहुँच गया, फिर भी इसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह 52% जनसंख्या के रोजगार का स्त्रोत है। औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और उपलब्धि भी कृषिगत कच्चे माल पर ही निर्भर करती हैं ।

भारत के कुल 328.726 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से 195.10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र 2009-2010 पर कृषि की जाती हैं, जबकि इसमें से 141.36% मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र (Net Sowing Area) हैं 46.29% अर्थात् यहाँ वास्तविक रूप से कृषि होती है । गत 60 वर्षो में शुद्ध बुआई क्षेत्र में तीव्रगति से वृद्धि हुई हैं । वर्ष 1950-51 में इसके अधीन केवल 118.75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था ।

असंगठित क्षेत्र के कुल श्रम बल का 90% से भी अधिक लोगों को कृषि क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है।

- श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 45% लोग कृषि पर निर्भर हैं।
- वर्ष 2021 - 22 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.9% रही है।
- जबकि 2020 - 21 में यह वृद्धि दर 3.6% रही थी।

स्थानित तौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र का 55% से अधिक प्रतिवेदित क्षेत्र (Reported Area) शुद्ध बुआई क्षेत्र के रूप में पाया जाता हैं । कृषि की दृष्टि से ये देश के अग्रणी क्षेत्र हैं।

विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम

एरोपोनिक	पौधों को हवा में उगाना
एपीकल्चर	मधुमक्खी पालन
हॉर्टीकल्चर	बागवानी
फ्लोरीकल्चर	फूल विज्ञान
ओलेरीकल्चर	सब्जी विज्ञान
पोमोलॉजी	फल विज्ञान
विटीकल्चर	अंगूर की खेती
वर्मीकल्चर	केंचुआ पालन
पिसीकल्चर	मत्स्यपालन
सेरीकल्चर	रेशम उद्योग
मोरीकल्चर	रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना

कृषि के अन्य प्रकार एवं प्रतिरूप :-

भारत में भौगोलिक स्थितियों में विभिन्नताएं पायी जाती है। इसी प्रकार अलग-अलग क्षेत्रों में जलवायु विभिन्नता भी देखने को मिलती है। इस कारण से भारत में कई प्रकार की खेती / कृषि की विधियाँ प्रचलित हैं -

झूम कृषि - पूर्वोत्तर क्षेत्र में, वनों को जलाकर की जाती है।

गहन कृषि – कृषि आगतों का अधिक उपयोग। गहन कृषि को सघन कृषि भी कहा जाता है, इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं । भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि देखी जा सकती है । सामान्यतः 200% से अधिक सस्य गहनता वाले क्षेत्र को गहन कृषि क्षेत्र माना जाता है।

विस्तृत कृषि - बड़े भूखण्डों (जोतों) में की जाने वाली कृषि।

बागानी कृषि - पहाड़ी ढालों के सहारे बागानों में की जाने वाली कृषि। बागानी कृषि एक प्रकार की पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्यों से की जाने वाली कृषि है, जिसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है।

जीवन-निर्वाह कृषि - जीवनयापन के उद्देश्य से।

मिश्रित कृषि - कृषि के साथ पशुपालन।

सतत् कृषि - पारिस्थितिकी के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कृषि

मिश्रित कृषि - दो-या-दो से अधिक फसलों को एक साथ या फसलों के उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन भी मिश्रित कृषि है।

स्थानांतरित कृषि :- इसमें सर्वप्रथम कुल्हाड़ी से वन के किसी खंड को साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर यहीं क्रिया की जाती है। इसे काटना और जलाना अथवा बुश फेलो कृषि भी कहा जाता है। खेतों का आकार छोटा होता है तथा एक साथ कई फसलों की कृषि की जाती है ।

अंतराफसलीकरण - दो-या-दो से अधिक फसलों को एक साथ एक निश्चित पैटर्न पर उगाना।

फसल चक्र - परिपक्वता के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र।

भारत की फसल ऋतुएँ

भारत की भौतिक संरचना, जलवायविक (Climatic) एवं मृदा संबंधी विभिन्नताएँ ऐसी हैं, जो विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करती हैं। देश के उत्तरी एवं आंतरिक भागों में तीन प्रमुख फसल खरीफ, रबी व जायद के नाम से जानी जाती हैं।

1. खरीफ

ये वर्षा काल की फसलें हैं, जो जून - जुलाई में दक्षिण - पश्चिम मानसून के प्रारम्भ होने के साथ बोई जाती है तथा सितम्बर-अक्टूबर तक काट ली जाती है । इसमें उष्णकटिबन्धीय फसलें शामिल हैं, जिसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सनई, तम्बाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि की कृषि की जाती है।

2. रबी

ये फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं। इस समय का कम तापमान शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धीय फसलों के लिए सहायक होता है। इस ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। इसके अंतर्गत शामिल प्रमुख फसलें-गेहूँ, जौं, चना, मटर, सरसों, राई आदि हैं।

3. जायद

जायद एक अल्पकालिक एवं ग्रीष्मकालीन ऋतु फसल है, जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अर्थात् अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। इसमें सिंचाई की सहायता से सब्जियों तथा खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि की कृषि की जाती है। मूंग एवं कुल्थी जैसी दलहन फसलें भी इस समय उगाई जाती हैं। यद्यपि इस प्रकार की पृथक् फसल ऋतुएँ देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती। यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल (Tropical Crop) की बुआई में सहायक है, इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही फसल तीन बार उगाई जा सकती है।

कृषि ऋतु	प्रमुख फसलें
उत्तरी भारत राज्य / दक्षिणी भारत खरीफ (जून से सितम्बर)	चावल, कपास, बाजरा,चावल, रागी, मक्का, ज्वार, अरहर (तुर) तथा मूंगफली
रबी (अक्टूबर से मार्च)	गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौं चावल, मक्का,रागी,
जायद (अप्रैल से जून)	वनस्पति, सब्जियाँ, फल, चावल, सब्जियाँ, चारा, चारा फसलें

कृषि के स्थानीय नाम

राज्य/क्षेत्र	स्थानीय नाम
पूर्वोत्तर, असम	झूम
केरल	पोनम
ओडिशा/आन्ध्र प्रदेश	पौंडु
मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़	बीवार, वीरा, पेंडा, मशान
दक्षिणी –पूर्वी राजस्थान	वालरा

प्रमुख फसलें

भारत में प्रमुख फसलों की कृषि

1. चावल –

- यह प्रेमिनी कुल की एक उष्णकटिबंधीय फसल है एवं भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी अच्छी

कृषि की जाती है। चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु की उपयुक्तता के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है।

- देश में सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47% भाग पर चावल की कृषि की जाती है।
- विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र (28%) भारत में हैं जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2012 में चावल निर्यात में भारत का विश्व में प्रथम स्थान था। 2022 में भी प्रथम ही है ।
- भारत में विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 21% चावल पैदा होता है।
- कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के 'चावल के कटोरे' के नाम से भी जाना जाता है।
- चावल के लिए भौगोलिक दशाएँ चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु 75 सेमी. से 200 सेमी. तक वर्षा एवं प्रारंभ से तापमान 20^0 C तथा बाद में 27^0 C हो जाता है ।
- भारत में चावल की तीन फसलें - अमन (शीतकालीन) ओस शरदकालीन तथा बारो (ग्रीष्मकालीन) पैदा की जाती है। वर्ष मे सबसे अधिक अमन का उत्पादन होता है जो जून से अगस्त तक बोई एवं नवम्बर से जनवरी तक काट ली जाती है।
- यहाँ विभिन्न राज्यों में पैदा की जाने वाली चावल की कुछ विशेष किस्में इस प्रकार हैं- साम्बा, कुरुंबई (तमिलनाडु) कामिनी, कालाजीरा, गोविंदभोग (पश्चिम बंगाल), जरीसाल (गुजरात), बासमती (उत्तर प्रदेश)। पश्चिमी बंगाल व तमिलनाडु में चावल की तीन फसलें उगाई जाती है, ओस (सितम्बर - अक्टूबर) अमन (जाड़ा) एवं बोरो (गर्मी)। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति 'जया' थी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र कटक (ओड़िसा) में है।
- वर्तमान समय में चावल की अधिक उपज देने वाली कई किस्में विकसित की गई है, ये हैं IR-8, IR-20 साकेत, सरजू, महसूरी, गोविन्द, पूसा-2-21, गौरी, श्वेता, चिंगम, धनु, RH-204, GR8, साबरमती, पूसा-33, रत्ना, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, तेलाहम्सा, हम्सा, बाला, PLA, I. किरन आदि। कीट रोधी किस्में-IET-144, बाला एवं N-2 है।
- वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन (आनुवांशिक परिवर्तन) करके विटामिनों की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है, इस चावल का नाम 'गोल्डन राइस' रखा गया है।
- गोल्डन राइस को पैदा करने के लिए उसके पौधों पर जीनों का प्रत्यारोपण करना पड़ता हैं, जिससे पौधा बीटा कैरोटिन युक्त पीले रंग का चावल उत्पादित करता है।
- देश में चावल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन अभी भी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम (1741 किग्रा.) में है, जबकि जापान में 6240 किग्रा. प्रति हैक्टेयर चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल (14245) पंजाब (11%), उत्तरप्रदेश (12.36%) का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है।

2. गेहूं (Wheat) –

- यह प्रेमिनी कुल का सदस्य है। विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है चावल के बाद देश का दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।
- देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% एवं कुल बोए गए क्षेत्र के 13% भाग में गेहूँ की कृषि की जाती है।
- गेहूँ कुल बोये गये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है।
- चावल की अपेक्षा इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन (लगभग 2770 कि.ग्रा) अधिक है। इसकी अधिकांश कृषि सिंचाई के सहारे की जाती है।
- भारत में विश्व का लगभग 12.5 प्रतिशत गेहूँ का उत्पादन होता है।
- आर्थिक समीक्षा 2011-12 के अनुसार देश में गेहूँ की औसत उपज 29.38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
- हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर ही पड़ा है। हरित क्रांति के अधिक प्रभाव गेहूँ पर पड़ा है इसके पश्चात् गेहूँ के उच्च उत्पादकता एवं उत्पादन प्राप्त किया गया है।
- गेहूँ के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ उपजाऊ मिट्टी, 50 सेमी. से 75 सेमी. तक वर्षा, आरंभ में तापमान 10°C से 15°C तथा बाद में 20°C से 25°C है। गेहूँ में सामान्यतः प्रोटीन 8-15%,

- Trade defficient (Export ↓)
- श्रमदर में वृद्धि

अवगुण - वंदना शिवा के अनुसार भारत में हरित क्रांति ने प्रादेशिक विषमता, एवं अंतर-राज्यीय एवं अंतर्राज्जीय विषमताओं को जन्म दिया | क्योकिं यदि प्रत्येक राज्य के उत्पादन मे आंशिक वृद्धि भी होती तब भी सकल उत्पादन हरित क्रांति के लाभ के बराबर होता है।

- पूंजीवादी कृषि का उदय
- कृषि का वाणिज्यीकरण
- रोजगार सृजन
- वर्ग विभेद उत्पन्न हुआ
- सीमान्त एवं लघु किसान भूमिहीन श्रमिक बन गये
- ग्रामीण ऋणग्रस्तता
- मशीनीकरण के कारण ग्रामीण बेरोजगारी

सामाजिक प्रभाव –

- दहेज प्रथा
- ग्रामीण विकलांगता (मशीनों के कारण)
- ग्रामीण शांति वत्य (Rural Tranquility)
- सामाजिक सौहार्द ख़त्म
- अर्थव्यवस्था, उपभोक्तावादी समाज का उदय

1961 - State in low and order में प्रथम स्थान पर (बिहार)
पूर्वी UP भी GOP (कृषि) – UP बिहार

पर्यावरणीय प्रभाव -

मृदा तंत्र से संबंधित - लवणीकरण - सुपोषण
- लवनीकरण - अमलीकरण - मृदा क्षरण
- रेह, कल्लर, मृदा का निर्माण
- N_2 मे वृद्धि से पारिस्थितिक तन्त्र ख़त्म, जलतन्त्र ख़त्म, जलकुम्भी ख़त्म

जल तंत्र पर प्रभाव –

ट्यूबबेल सिंचाई के कारण As, Pb की मात्रा बढ़ना - सतही जल का लवणीकरण-सुपोषण विषाक्तता - भूमिजल विषाक्तता - जलस्तर में गिरावट - समुद्र जल का भूमि क्षेत्र में प्रवेश

कृषि पारिस्थितिक तन्त्र पर प्रभाव

- निर्वनीकरण (UP, Pb मे बेहद स्तर पर)
- खरपतवार नाशकों के प्रयोग से पारिस्थितिक विभिन्नता
- टिड्डा दल का आक्रमण (पहले वनों पर आश्रित रहते थे लेकिन वनों की कमी के कारण फसलों पर आक्रमण)
- चरागाह क्षेत्र मे कमी

प्रदूषण - जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण

• सिंचाई

I. सिंचाई के साधन: एक परिचय

- किसी भी देश में कृषि विकास पर्यावरणीय, राजनीतिक, संस्थात्मक एवं आधारभूत संरचनात्मक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। आधारभूत संरचनात्मक कारकों के अंतर्गत सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, रासायनिक एवं जैविक उर्वरक, उन्नत बीज इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये कारक समष्टि एवं व्यष्टि, दोनों स्तरों पर विशिष्ट भूमिका का निर्वाहन करते हैं।
- सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा खेतों को जल उपलब्ध कराना है। अतः नहर, कुएं, नलकूप, तालाब आदि साधनों के माध्यम से फसलों को जल आपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। फसलों की वृद्धि, शुष्क क्षेत्रों में असंतुलित मृदा (disturbed soils) में पौधों के पुनः विकास तथा अपर्याप्त वर्षा के दौरान जल आपूर्ति के लिए सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत सीधे वर्षा जल पर आश्रित कृषि को वर्षा सिंचित कृषि कहते हैं। इसके अलावा बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित नमी को संचित करके तथा बिना सिंचाई वाली कृषि शुष्क भूमि कृषि कहलाती है।
- प्राचीन काल से ही मानव जाति सिंचाई प्रणाली से लाभान्वित हो रही है। पुरातत्त्व संबंधी जांच में उन स्थानों पर सिंचाई के प्रमाण मिले हैं जहाँ फसल उत्पादन के लिए प्राकृतिक वर्षा अपर्याप्त थी। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया के मैदानी क्षेत्रों में बारहमासी सिंचाई की जाती थी, सीरिया में सीढ़ीदार खेत सिंचाई, मिस्र में बेसिन सिंचाई आदि। 20वीं शताब्दी में डीजल और इलेक्ट्रिक वाटर पंप मोटरों के आगमन के पश्चात् मनुष्यों ने

भूजल का अधिकाधिक दोहन कर एवं नहरों आदि को विस्तृत कर सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि की।

- भारतीय मानसून की प्रकृति अत्यंत अनियमित होती है। मानसून की विफलता की स्थिति में फसल नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है लेकिन कम वर्षा से फसल उत्पादन में काफी कमी हो सकती है तथा चरम दशाओं में फसल पूर्णतया नष्ट हो सकती है। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा सिंचित कृषि की जाती है।
- भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है तथा ऐसा अनुमान है कि बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए भारत को अनाज के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष 2050 में जल की मांग वर्ष 2000 की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक होने का अनुमान है, वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थों की मांग भी दोगुना होने का अनुमान है। औसतन, एक टन अनाज का उत्पादन करने के लिए लगभग एक हजार टन जल की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक अनियमित जलवायु दशाएँ उत्पन्न होंगी और इस प्रकार फसलें वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक प्रवण हो जाएंगी। सिंचित भूमि की वर्तमान उत्पादकता 2.5 टन हेक्टेयर है तथा वर्षा सिंचित कृषि भूमियों की उत्पादकता 0.5 टन हेक्टेयर से भी कम है। इस संदर्भ में, सिंचाई रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की एक त्वरित आवश्यकता है।
- भारत विश्व की नदियों के कुल औसत वार्षिक जल प्रवाह का 4% प्राप्त करता है। प्राकृतिक जल प्रवाह की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम से कम 1100 घन मीटर प्रति वर्ष है। जल की मात्रा जो वास्तव में लाभदायक उपयोग के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, वह मात्रा भौतिक एवं स्थलाकृतिक अवरोधों, अंतरराज्यीय मुद्दों और वर्तमान प्रौद्योगिकी द्वारा आरोपित कठोर प्रतिबंधों के कारण बहुत कम है।

<u>जल संसाधन</u>

इस पृथ्वी पर जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक संसाधन हैं। इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहीं तरह से करते है पीने से लेकर कृषि कार्य , औद्योगिक क्षेत्र , आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों में करते हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार हमारे देश में कुल 1869 घन किमी. जल उपलब्ध हैं। भारत में उपलब्ध जल को 2 भागों में बाँटा जा सकता है वह हैं -

1. भू-जल /भौम जल
2. धरातलीय जल / सतही जल

1. <u>भू – जल / भौम जल :-</u>

वर्षा से जो जल हमें प्राप्त होता हैं, उसका कुछ भाग मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है / जिससे यह जल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भू – स्तर तक पहुँच जाता हैं इसी जल को भू – जल या भौम जल कहा जाता है जिसे हम कुएँ, ट्यूबवेल आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है / धरती पर अधिकांश अलवणीय जल बर्फ , हिमनद के रूप में पाया जाता है तथा बाकी शेष भाग भू – जल के रूप में होता हैं/

भूमिगत जल की उपलब्धता वर्षा की मात्रा, वर्षा की प्रकृति, भूमि के स्वभाव तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है।

अधिक वर्षा वाले भागों में जहाँ भूमि समतल तथा सरंध्र मृदा वाली है वहाँ पानी आसानी से रिस जाता है। अतः इन क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहराई पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

गंगा - ब्रह्मपुत्र के मैदानों तथा तटीय मैदानों में **भौम** जल के विशाल भंडार हैं।

प्रायद्वीपीय पठार, हिमालयी क्षेत्रों तथा मरुस्थलीय भागों में भूमिगत जल कम मात्रा में मिलता है।

भारत के प्रायद्वीप भाग पर कठोर तथा अप्रवेश्य चट्टानों के कारण भूमिगत जल का आभाव पाया जाता है/ भूमिगत जल का लगभग तीन – चौथाई भाग सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है देश में भूमिगत जल का अत्याधिक दोहन से इसका स्तर काफी नीचे चला गया है/

2. <u>धरातलीय जल या सतही जल :-</u>

नदियों , झीलों , तालाबों तथा अन्य जलशयों में पाया जाने वाला जल सतही या धरातलीय जल कहलाता है/ नदियों में जल हिम के पिघलने से या फिर वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है/ सतही जल की कुल मात्रा का सर्वाधिक भाग नदियों में पाया जाता है / देश में समस्त सतही जल का लगभग 60 प्रतिशत भाग इन तीन प्रमुख नदियों सिंधु,

गंगा, तथा ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है/ विश्व की समस्त नदियों में प्रवाहित होने वाले जल का 6 प्रतिशत भारत की नदियों में प्रवाहित होता है/

जल संसाधन का उपयोग

भू - जल एवं सतही जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है/ देश में भूमि जल का 92 प्रतिशत तथा सतही जल का 89 प्रतिशत भाग केवल कृषि कार्यों के उपयोग में लिया जाता है / जबकि औद्योगिक क्षेत्र में यह 2 से 5 प्रतिशत तक ही सीमित है। कृषि क्षेत्रों की कार्यों के लिए उपयोग में लिया गया जल का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है लेकिन वर्तमान समय जनसंख्या एवं नगरीकरण के विकास के साथ अन्य क्षेत्रों में भी जल का उपयोग बढ़ा है/

जल संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण

जल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए जल के संरक्षण की अति आवश्यकता है ।जल के संरक्षण का मुख्य उद्देश जल स्त्रोतों को होने वाले ह्रास से बचाना तथा बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है / तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिक क्षेत्रों से फैलता प्रदूषण एवं जल संसाधनों की घटती संख्या, मौसम चक्र में परिवर्तन तथा आने वाले भविष्य के कारण इसका संरक्षण ज़रूरी हो गया है।

जल संरक्षण के लिए कुछ उपाय :-

- जल का पुनः चक्रण करके
- भू - जल तथा वर्षा जल को एकत्रित करके
- धरातलीय जल का संग्रहण करके
- सिंचाई पद्धति में परिवर्तन करके
- कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करके

सिंचाई के स्त्रोत

1. भारत में सिंचाई के स्त्रोत -

- नहरों द्वारा - 31. 4%
- तालाबों द्वारा - 4. 7%
- कुओं द्वारा - 22. 1 %
- नलकूपों द्वारा - 36. 6 %
- अन्य साधन - 5. 0 %

नहरी सिंचाई

नहरें भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। भारत की कुल सिंचित भूमि का 36 प्रतिशत क्षेत्र नहरों द्वारा ही सींचा जाता है। अधिकांश नहरें उत्तर - पश्चिम भारत के मैदानी भाग में है। इस भाग में अधिकतर नहर होने के निम्नलिखित कारक हैं –

1. यहां पर बहने वाली नदियां हिमालय के हिमाच्छादित भागों से निकलती है, जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। यहां की मृदा कोमल और मुलायम है, जिससे नहरों को आसानी से खोदा जा सकता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, परंतु वर्षा की मात्रा कम है। अतः कृषि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नहरों की आवश्यकता होती है।
2. सतलुज - गंगा मैदानी क्षेत्र में नहरों द्वारा व्यापक रूप से सिंचाई की जाती है।
3. नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार U.P में है इसके अलावा MP, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि राज्यों में भी नहरों से सिंचाई होती है।
4. इस भाग में ढाल काफी मंद है और नहरों को नलकूप ढाल के सहारे दूर-दूर तक ले जाएँ जा सकते हैं।

नहरी सिंचाई मैदानी भागों में अधिक है जबकि पठारी भागों में कम (कारण)

1. प्रायद्वीपीय चट्टान कठोर होने के कारण उसका कटान आसानी से संभव नहीं है।
2. पठारी भागों की नदियां वर्षवाहिनी नहीं है।
3. पठारी भाग में कृषि क्षेत्र का आकार छोटा है तथा कृषि वितरण भी असमान है /

1. देश की प्रमुख नहरें

– 97 में त्वरित सिंचाई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है/ इसके अंतगर्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं / इस कार्यक्रम के अंतगर्त पिछड़े क्षेत्रों के लिए कुल सहायता राशि का 90% अनुदान के रूप में होता हैं सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए 5 वीं पंचवर्षीय योजना से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जल उपयोग के लिए दक्षता के विकास के लिए 1974 – 75 में प्रारंभ किया गया हैं जिसके घटक निम्न हैं-

- जल का न्याय पूर्ण वितरण हो/
- विद्युत परियोजना परिवहन भंडारण विपणन ऋण बीमा आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना/
- सिंचाई के लिए पक्की एवं मज़बूत नहरों का निर्माण करवाना ताकि जल का रिसाव ना हो सके /
- अधिक उत्पादन के लिए hyv बीज, उर्वरक, खाद आदि आधुनिक कृषि आगत उपलब्ध कराना हैं/
- कृषि कार्य के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना /
- सतही जल तथा भूमि जल दोनों का समन्वित करना /
- बंजर भूमि का पुनरुद्धार करना /

वर्तमान समय में 332 परियोजनाएँ चलाई जा रही जिसके तहत् 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आता हैं/

❖ नदी जोड़ों परियोजना :-

देश में जल संसाधन के वितरण में काफी असामनता पाई जाती हैं/ उत्तर तथा पूर्वी भारत के नदियों में जल की अधिकता के लिए प्रत्येक वर्ष बाढ़ की समस्याएँ आ जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत व पश्चिम भारत की नदियों में जल के कमी के कारण सूखे की आंशका होती हैं/ ऐसे समस्याओं को दूर करने के लिए नदी जोड़ों परियोजनाओं को शुरू किया है जिससे कम जल वाले नदियों को अधिकतम जल वाले नदियों से जोड़ना हैं/

लाभ

- कहीं शहरों तक पेयजल की आपूर्ति किया जा सकता है
- 34 मिलियन किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा/
- बाढ़ नियंत्रण में सुविधा होगी/
- 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार दिया जाएगा /

समस्याएँ

- परियोजना की लागत बहुत अधिक है
- 15 लाख से अधिक जनसंख्या का विस्थापन होगा भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याएँ जनित होंगी ।
- नेपाल एवं भूटान से सहयोग की आवश्कता होगी।
- विषम उच्चावच के कारण जल को लिफ्ट करने में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी /

प्रमुख बहु – उद्देशीय परियोजनाएँ :-

बहु – उद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश नए प्रबंधन का विकास कारण, जल विद्युत के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना , बाढ़ वाले क्षेत्र पर नियंत्रण करना,तथा मछली पालन में विकास करना होगा /

देश की प्रमुख बहु- उद्देशीय नदी घाटी परियोजना कुछ इस प्रकार है-

परियोजना का नाम	नदी	लाभान्वित राज्य
भांगड़ा – नांगल	सतलज नदी	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
नागार्जुन सागर	कृष्णा नदी	आंध्र प्रदेश
चंबल	चंबल नदी	राजस्थान ,मध्य प्रदेश
हीरा कुंड बांध	महानदी	ओड़िसा
व्यास	व्यास नदी	राजस्थान, पंजाब हरियाणा
दामोदर	दामोदर नदी	झारखण्ड, पश्चिम बंगाल
तवा	तवा नदी	मध्य प्रदेश
मालप्रभा	मालप्रभा नदी	कर्नाटक
नागपुर शक्तिगृह	कोरडी नदी	महाराष्ट्र

काकड़ापारा	ताप्ती नदी	गुजरात
कोसी नदी	कोसी नदी	बिहार, नेपाल
तुंगभद्रा	तुंगभद्रा नदी	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
मयुरक्षी	मयुरक्षी नदी	पं. बंगाल
फरक्का	गंगा नदी	पं . बंगाल
गंडक	गंडक नदी	बिहार, नेपाल
कुंडा	कुंडा नदी	तमिलनाडु
कोयना	कोयना नदी	महाराष्ट्र
टिहरी	भागीरथी नदी	उत्तराखंड
माताटीला	बेतवा नदी	उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश
भीमा परियोजना	पवना नदी	महाराष्ट्र
शारदा	गोमती , शारदा नदी	उत्तर प्रदेश
नाथपा – झाकरी	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश
कोल डैम	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश
शरावती	शरावती नदी	कर्नाटक
इंदिरा गाँधी	सतलज नदी	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
उकाई	ताप्ती नदी	गुजरात
पंचेत बांध	दामोदर नदी	झारखण्ड , पं. बंगाल
पूर्णा	पूर्णा नदी	महाराष्ट्र
गिरना	गिरना नदी	महाराष्ट्र
हंस देव बांगो	हंसदेव नदी	मध्य प्रदेश
सतलज	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर
भद्रा	भद्रा नदी	कर्नाटक
ऊपरी कृष्णा	कृष्णा नदी	कर्नाटक
इडुक्की	पेरियार नदी	केरल
रिहंद	रिहंद नदी	उत्तर प्रदेश
दुर्गा बैराज	दामोदर नदी	झारखण्ड, पं. बंगाल
बरगी	बरगी नदी	मध्य प्रदेश
हिडकल	घटप्रभा नदी	कर्नाटक
जायकवाड़ी	गोदावेरी नदी	महाराष्ट्र
रंजीत सागर बांध	रावी नदी	पंजाब
कांगसावती	कांगसावती नदी	पं. बंगाल
रामगंगा	रामगंगा नदी	उत्तर प्रदेश
तुलबुल	झेलम नदी	जम्मू - कश्मीर
राणा प्रताप सागर	चंबल नदी	राजस्थान
जवाहर सागर	चंबल नदी	राजस्थान
नर्मदा घाटी	नर्मदा नदी	मध्य प्रदेश, गुजरात
गाँधी सागर	चंबल नदी	मध्य प्रदेश
सरहिंद नहर	सतलज नदी	हरियाणा
सरदार सरोवर	नर्मदा नदी	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , गुजरात
तिलैया	बराकर नदी	झारखण्ड
दुलहस्ती	चिनाब नदी	जम्मू - कश्मीर

➢ **बहुउद्देशीय परियोजनाएँ :-**

शिवसमुद्रम परियोजना	कावेरी नदी	कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल
मचकुण्ड	मचकुण्ड नदी	आंध्रप्रदेश व ओड़िसा
पोचम्पाद	गोदावरी	कर्नाटक
सलाल	चिनाब	जम्मू कश्मीर
टनकपुर	महाकाली नदी	भारत - नेपाल सीमा (उत्तर

परीक्षोंपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक में तीन घटक- सकल घरेलू (GDP)उत्पाद की वृद्धि दर, जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग को शामिल किया जाता है ।
- जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक(PQLI) का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्रमशः 100 तथा 1 होता है ।
- राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक के परिकलन में उपभोग व्यय एवं शैक्षिक सूचकों का उपयोग करते हैं ।
- शिक्षा विकास सूचकांक 2012-13 में उच्चतम रैंक पर लक्ष्यद्वीप एवं न्यूनतम रैंक पर झारखंड का था।
- मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्यप्रदेश था ।
- मानव विकास सूचकांक(HDI) का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्रमशः 0 से 1 था ।
- मानव विकास रिपोर्ट, 2019 में शीर्ष राष्ट्र में नॉर्वे का स्थान प्रथम है ।
- मानव विकास रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा । तथा सबसे निचले स्थान पर सोमालिया रहा ।
- मानव विकास रिपोर्ट, 2019 में सबसे निचले स्थान पर नाइजर का नाम है ।
- मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(UNDP) द्वारा जारी किया जाता है ।
- पूंजी निर्माण के तीन आवश्यक घटकों में बचत, बचत के गतिशीलन हेतु वित्तीय संस्थाएँ तथा विनियोग को शामिल किया जाता है
- भारत में पूंजी निर्माण आँकड़ें एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है ।
- दीपक पारेख समिति आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से संबंधित हैं ।
- औद्योगिक प्रगति बिजली उत्पादन, परिवहन एवं संचार जैसी आधारभूत संरचना के विकास पर निर्भर करती हैं ।

  किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हैं ।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

RAS Mains गत वर्ष प्रश्न

प्रश्न.-1. औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। (2022)

प्रश्न.-2. 1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किये गये। स्पष्ट कीजिए? (2022)

प्रश्न.-3. भारत में अवसंरचना ढांचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। (2022)

प्रश्न.-4. आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के विभिन्न मापक बताइये।

प्रश्न.-5. वैश्वीकरण को समझाइये?

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 4

मुद्रास्फीति – कीमतें और मांग / पूर्ति प्रबंधन

- परिभाषा- वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में निरंतर बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहते हैं।
- मुद्रास्फीति हमारे बजट को प्रभावित करती है। इसके कारण किसी भी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है। वास्तव में मुद्रा के क्रय क्षमता में उत्पन्न इस कमी को ही मुद्रास्फीति कहते हैं।
- प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने मुद्रास्फीति की तुलना ऐसे डाकू से की है जो कि अदृश्य रहता है।
- मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव समाज के निम्न वर्ग पर पड़ता है। मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के पास अधिवर्ष होता है। जिसे किसी संपत्ति में निवेश किया जा सकता है। जैसे - मुद्रास्फीति के कारण उपभोग महंगा होगा। उस संपत्ति के मूल्य में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी जो कि मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को निरस्त कर देगी। चूंकि मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी को संबोधित करती है।
- हर वह मुद्रा जिसकी क्रय क्षमता शुन्य हो जाती है उसे परिचालन से बाहर कर दिया जाता है। वर्तमान में 50 पैसा वह न्यूनतम मूल्य की मुद्रा है जिसका भारत में वैधानिक प्रयोग किया जा सकता है। परंतु इसका प्रयोग ₹10 तक के भुगतान के उपभोग तक ही किया जा सकता है। यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़े तब ऐसी स्थिति में देने वालों को घाटा होता है। जबकि ऋणी को लाभ होता है।

मुद्रा की मात्रा	= वृद्धि
मुद्रा का मूल्य	= कमी
समग्र मांग	= वृद्धि
समग्र पूर्ति	= कमी
वस्तुओं का मूल्य	= वृद्धि

मुद्रास्फीति के प्रकार - कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. Demand push inflation (मांग प्रेरित मुद्रास्फीति)
2. Cost push inflation (लागत प्रेरित मुद्रास्फीति)
3. Structural inflation (संरचनात्मक मुद्रास्फीति)

यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में Demand Push Inflation (मांग प्रेरित मुद्रास्फीति)

- बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता (मुद्रा की आपूर्ति) ज्यादा हो या तो आय में बढ़ोतरी के कारण अथवा बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति के कारण तब उपभोक्ता का उपभोग बढ़ता है। यदि इस बढ़ते हुए उपभोक्ता मांग की सही मात्रा में सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी।
- यदि मांग में बढ़ोतरी के कारण सकल मांग, सकल आपूर्ति को पार कर जाए तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में चूंकि रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न होते हैं। इस बढ़ते रोजगार के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
- मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आर्थिक संवृद्धी से भी संबंधित होती है क्योंकि बढ़ती हुई मांग उत्पादन को भी बढ़ावा देती है।
- किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर को कम करने का प्रयास किया जाता है। परंतु बेरोजगारी की दर उसी गति से कम की जाती है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण से बाहर ना कर दे।
- इसे NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) कहते हैं।

लागत प्रेरित मुद्रास्फीति

- प्रत्यक्ष तौर पर मांग नहीं परंतु अप्रत्यक्ष तौर पर मांग होती है। यह मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न नहीं होती है।
- लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात कच्चे माल अथवा किसी भी अन्य प्रकार की लागत में बढ़ोतरी हो जाए तब अंतिम उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवा स्वतः महंगी हो जाती है। उदाहरण स्वरुप डीजल जो कि परिवहन एवं उत्पादन की प्रक्रिया में इंधन का एक प्रमुख स्रोत है, महंगा हो जाए तब अंतिम उत्पादित वस्तु स्वतः महंगी हो जाएगी।

Structural Inflation (संरचनात्मक मुद्रास्फीति)

- यह किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। अन्य शब्दों में यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधाओं में कमी हो एवं इससे मुद्रा स्थिति उत्पन्न हो तब यह संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है।
- संरचनात्मक मुद्रास्फीति जमाखोरी (Hoarding), व्यवसायिक समूह करण (Cartelization), कालाबाजारी (Black Marketing) इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है।

- **जमाखोरी (Hoarding)** – यदि एक व्यापारी अथवा बिचोलिया किसी वस्तु को उत्पादक से अत्यधिक मात्रा में खरीद कर उसे बाजार तक न पहुँचने से लंबे समय तक उस वस्तु को अपने गोदाम में रख ले, जिससे बाजार में उस वस्तु की कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाए। तब यह जमाखोरी कहलाती है।
- **व्यवसायिक समूह करण (Cartelization)** – किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मांग एवं आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। यदि इन वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर आपसी सहमति से मूल्यों में बढ़ोत्तरी कर दी। तब यह व्यवसायिक समूह करण कहलाता है।
- **कालाबाजारी (Black Marketing)** – यदि एक अनिवार्य वस्तु जिसे सरकार सस्ते मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। परंतु विक्रय वस्तु को बाजार में उच्च मूल्य पर बेच दे तब यह कालाबाजारी कहलाती है।

- भारत क्योंकि एक विकासशील देश है रोजगार के अवसरों के उत्पन्न होने के कारण मांग प्रेरित मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है।
- भंडारण एवं वितरण की सुविधाओं में कमी के कारण संरचनात्मक मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि कच्चे माल अथवा अन्य संसाधनों की कमी के कारण लागत पर मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है।
- भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण की जिम्मेदारी RBI की है। परंतु आरबीआई मात्र मांग आधारित स्थिति को ही उचित रूप से नियंत्रण नियंत्रित कर सकती है। लागत प्रेरित एवं संरचनात्मक मुद्रा स्फीति पर का नियंत्रण नहीं होता है। अतः केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग के बिना मुद्रास्फीति का नियंत्रण संभव नहीं है।

दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति जिस दर से बढ़ती है उस आधार पर इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मुद्रास्फीति के प्रकार	दर
सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति (Galloping inflation)	10 – 20%
भागती हुई मुद्रास्फीति (Runaway Inflation)	100 – 200%
अति मुद्रास्फीति (Hyper Inflation)	1000%

<u>मुद्रा संकुचन / अपस्फीति (Deflation)</u> –

- यह मुद्रास्फीति का विपरीतार्थक अर्थात् मंहगाई का विलोम है।
- अपस्फीति वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की अवस्था को दर्शाती है। ऐसा मुख्यतः दो परिस्थितियों में देखा जाता है।
  1. यदि सकल आपूर्ति सकल मांग को पार कर जाए
  2. यदि सकल मांग सकल आपूर्ति से नीचे चली आए
- सामान्यतः मांग में कमी तरलता में कमी के कारण एवं बढ़ती बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होती है।
- जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरम पर पहुँच जाए जैसे कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं तब यह भी मांग में कमी को जन्म देती है।
- यदि देश की अधिकांश जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या हो जाए तब से भी मांग प्रभावित होती है।

<u>पुनर्स्फीती (Reflation) Or संस्फीति</u>

- जब निरंतर अपस्फीति के उपरांत वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज हो तब यह पुनर्स्फीती कहलाती है।

महत्त्वपूर्ण

RAS Mains गत वर्ष प्रश्न

प्रश्न.-1. माँग का नियम से क्या आशय है ? (2022)

प्रश्न.-2. संरचनात्मक मुद्रास्फीति को समझाइए।

प्रश्न.-3. CPI क्या है ? इसका आधार वर्ष क्या है ?

प्रश्न.-4. मुद्रा के विभिन्न कार्य बताइये ।

प्रश्न.-5. मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए ।

प्रश्न.-6. मुद्रास्फीति को थोक विक्रेता व उपभोक्ता दोनों दृष्टिकोण से मापा जाता है। दोनों दृष्टिकोणों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए ।

प्रश्न.-7. माँग और आपूर्ति का नियम समझाइये ?

प्रश्न.-8. माँग के नियम के अपवाद को उदाहरण सहित समझाइये ?

अध्याय – 5

केंद्र- राज्य वित्तीय संबंध

संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र- राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है । इसके अलावा इस विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं।

- केंद्र और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में कार्य क्षमता पर्याप्तता और उपयुक्तता को मुख्य सिद्धांत माना गया है। संविधान निर्माताओं ने इन तीनों सिद्धांतों में समन्वय करने की अद्भुत चेष्टा की है।
- वित्त आधुनिक प्रशासन तंत्र का रक्त है। योजनागत व्ययों एवं आपदाओं के समय राज्यों को वित्तीय संकट से मुक्ति पाने के लिये केंद्रीय अनुदान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के राज्यों को भी राजस्व प्राप्त हेतु केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है।
- स्विटजरलैंड के संविधान में वित्तीय संसाधनों का विभाजन भारत के विपरीत वर्णित है। वहाँ केंद्र राज्य के ऊपर निर्भर है क्योंकि केंद्रीय राजस्व का अधिकतर भाग राज्यों से प्राप्त होता है।

केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान-

संविधान का अनुच्छेद **275** संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है।

- अनुच्छेद 286, 287, 288 तथा 289 में केंद्र तथा राज्य सरकारों को एक-दूसरे द्वारा कुछ वस्तुओं पर कर लगाने से मना किया गया है और उन्हें कुछ करों से भी मुक्ति प्रदान की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 292 तथा 293 क्रमशः संघ तथा राज्य सरकारों को शरण लेने का अधिकार भी प्रदान करते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 265 यह प्रबंध करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर शपथ या संग्रहित नहीं किया जा सकता।

- Note – इनको हमने बैंकिंग वाले अध्याय में विस्तारपूर्वक समझाया है ।

राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच महत्वपूर्ण अंतर

- सरकार की नीति जिसमें वह अपनी कर राजस्व और व्यय नीति का उपयोग करती है, कुल उत्पादों की मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए और अर्थव्यवस्था को राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। वह नीति जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित और नियंत्रित करता है, उसे मौद्रिक नीति के रूप में जाना जाता है।
- राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है जबकि मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रशासित की जाती है।
- राजकोषीय नीति एक छोटी अवधि के लिए बनाई जाती है, आम तौर पर एक वर्ष, जबकि मौद्रिक नीति लंबे समय तक रहती है।
- राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को दिशा देती है। दूसरी ओर, मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता लाती है।
- राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित है, लेकिन मौद्रिक नीति उधार और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है ।
- राजकोषीय नीति का प्रमुख साधन कर की दरें और सरकारी व्यय हैं । इसके विपरीत, ब्याज दर और क्रेडिट अनुपात मौद्रिक नीति के उपकरण हैं।
- राजकोषीय नीति में राजनीतिक प्रभाव है । हालांकि, यह मौद्रिक नीति के मामले में नहीं है ।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

RAS Mains गत वर्ष प्रश्न

प्रश्न-1. राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं ?
प्रश्न-2. प्राथमिक राजकोषीय घाटे को समझाइए।
प्रश्न-3. राजकोषीय घाटे की अधिकता निवेश प्रवृत्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है । स्पष्ट कीजिए ।
प्रश्न-4. FRBM एक्ट को समझाइये ?
प्रश्न-5. 15 वें वित्त आयोग की प्रमुख टिप्पणीयों को बताइये ?
प्रश्न-6. सरकारिया आयोग की सिफारिशों को समझाइये ?

अध्याय – 6

बजट प्रवृतियाँ और राजकोषीय नीति

बजट

- बजट किसी भी शासन के अनुमानित आय-व्यय के लेखे को कहा जाता हैं।
- लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, वित्तीय व्यवस्था। शासन द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती हैं। यह धन कहाँ से आयेगा? और यह धन कहाँ-कहाँ खर्च होगा? यह सभी बातें सुविचारित तथा सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इसी व्यवस्था को बजट के नाम से जाना जाता हैं।

बजट का अर्थ

- स्पष्ट है कि शासन के अनुमानित आय-व्यय के लेखे को बजट कहा जाता हैं। यह लेखा एक वर्ष का हो सकता है या उससे अधिक वर्ष का भी हो सकता हैं। इस लेखे में वर्ष में विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का वर्णन रहता है, साथ ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी रहता है कि उसके लिए जरूरी धन कहाँ से आयेगा? नये करों का प्रावधान भी उसमें रहता हैं।

एक अच्छे बजट के मुख्य लक्षण या विशेषताएं

1 बजट एक निश्चित अवधि के लिए आय-व्यय का अनुमान है।

2 यह एक तुलनात्मक तालिका भी है, जिसमे प्राप्तियों व खर्चों की राशियों की तुलनात्मक विवेचना होती हैं।

3 यह सरकार के लिये धन उगाही और व्यय के लिये विधायिका का आदेश है।

4 यह प्रशासन के कार्यों का वित्तीय प्रतिवेदन है।

बजट के प्रकार (Types Of Budget)

(1) निर्माण के आधार पर (On the Basis of Construction):

i व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित बजट ।

ii कार्यपालिका द्वारा निर्मित बजट (भारत में यही प्रचलित हैं) ।

iii मण्डल या आयोग द्वारा निर्मित बजट (अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित हैं) ।

(2) स्वरूप के आधार पर (On the Basis of Format):

(A) लाइन आइटम बजट (Line-Item Budget):

यह बजट का परम्परागत रूप है । यह 18वीं-19वीं सदी में विकसित हुआ । इस बजट में वस्तुओं या मद का महत्व अधिक होता है । उन मदों या वस्तुओं पर खर्च से क्या उद्देश्य हासिल होगा, इस पर नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य अपव्यय, अधिक खर्च और बर्बादी को रोकना है ।

i. लाइन-आइटम बजटिंग में सार्वजनिक व्यय पर कठोर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य को प्रमुखता दी जाती है । इसमें बजट को सार्वजनिक खर्च पर नियन्त्रण रखने की विधि के रूप में देखा जाता है जिसका परिणाम वस्तुनिष्ठ बजट के रूप में सामने आता है ।

ii. इसमें व्यय की प्रत्येक मद को पंक्तिवार (लाइन) लिखा जाता है ।

iii. इसमें यह देखा जाता है कि जिस मद पर खर्च की स्वीकृति हुई है, वह उसी पर व्यय हो, यद्यपि लाइन आइटम बजट को इस वस्तुनिष्ठता के बजाय एक दूसरे रूप में भी बनाया जाता है । जिसमें एक मद का पैसा दूसरे मद में भी खर्च करने की अनुमति रहती है।

iv. इसमें खर्च की जाने वाली राशि पर जोर अधिक रहता है, उससे क्या परिणाम हासिल हुआ, उस पर नहीं ।

v. इसे अभिवर्धन बजट व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि बजट राशि सदैव पूर्व की अपेक्षा अधिक दी जाती है । वैसे यही बजट अन्य सुधारात्मक बजट जैसे शून्य बजट आदि का आधार होता है।

(B) कार्य निष्पादन बजट (Performance Budgeting):

- यह वर्ष 1930 की मंदी का परिणाम था ।
- सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुवर आयोग (1949) ने इसकी सिफारिश की थी और 1950 में राष्ट्रपति ट्रुमेन ने इसे अपनाया था ।
- निष्पादन बजट (Performance Budget) शब्दावली सर्वप्रथम हुवर कमीशन (1949) ने ही प्रयुक्त की थी ।
- हुवर आयोग ने कार्य, कार्यक्रम और क्रिया को बजट का आधार बनाने की सिफारिश की थी, जो कार्य निष्पादन बजट के 3 प्रमुख तत्व हैं ।
- यह बजट व्यय को सीधे उपलब्धियों से जोड़ देता है । यह व्यय के स्थान पर व्यय के उद्देश्य पर आधारित है । इससे बजट का स्वरूप लोकतांत्रिक हो जाता है । सरकारी गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं । व्यवस्थापिका को स्पष्ट हो जाता है कि सरकार कौन से कार्यक्रम या परियोजनाएं शुरू कर रही है । इससे अगले वर्ष इनकी प्रगति के बारे में वह प्रभावशाली ढंग से पूछ सकती है ।
- यह नवीन लोक प्रशासन की देन है और वित्तीय प्रशासन में सुधार का आवश्यक अंग है । इसे शुरुवात में कार्यात्मक बजट या गतिविधि-बजट कहा जाता था ।

भारत का बजटीय इतिहास

- बजट शब्द का प्रतिपादन फ्रांसीसी शब्द बूजे से हुआ है , जिसका अर्थ चमड़े का बैग होता है ।
- वर्ष 1733 ई . में इंग्लैण्ड में इस शब्द का प्रयोग जादू के पिटारे के अर्थ में किया गया था ।
- **भारत में बजट निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है ; जैसे**

✓ विगत वित्त वर्ष के वास्तविक आय - व्यय अनुमान
✓ चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान
✓ चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान
✓ आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान

- **भारत के बजटीय इतिहास के निम्नलिखित प्रमुख तथ्य**

➢ स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवम्बर , 1947 को पहले वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम द्वारा पेश किया गया था ।
➢ जॉन मेथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था ।
➢ गैर - हिन्दी भाषी होने के बावजूद सीडी देशमुख ने वित्तमंत्री रहते सुनिश्चित किया था कि बजट के सभी दस्तावेज हिन्दी में भी छपे । इससे पूर्व वे केवल अंग्रेजी में ही छपते थे
➢ मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह , विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह देश में चार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं , जो वित्त मंत्री पद पर भी काम

का बजट में व्यापक योगदान सरकार की कमियों को उजागर होने से रोकता था ।

- अतः पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे आयोग का गठन किया गया ।
- 1920 में गठित इस आयोग की संस्तुति के आधार पर 1924 में आम बजट एवं रेल बजट को पृथक् कर दिया गया आजादी के बाद स्थिति की पुन : समीक्षा की गई ।
- आम बजट एवं रेल बजट को अलग - अलग प्रस्तुत करने की यह प्रक्रिया 92 वर्षों तक जारी रही और अंततः बजट 2017-18 में इन दोनों का विलय कर दिया गया ।

बजट 2023-24

2023-24 का बजट अनुमान

- कुल प्राप्तियां (उधारी के अलावा)- 27.2 लाख करोड़
- कुल व्यय - 45 लाख करोड़
- नेट टैक्स प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़

बजट 2023 की खास बातें

- भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 रु. हुई।
- अगले एक साल तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी।
- पीएम सुरक्षा के तहत् 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा।
- बागवानी योजनाओं पर रहेगा जोर, 2200 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान।
- कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड रुपए किया जाएगा।
- 157 नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग हिस्सों में खोले जाएंगे।
- अनुसूचित जाति मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ खर्च होंगे।
- पीएम आवास योजना फंड में 66 फ़ीसदी की बढ़ोतरी।

बजट 2023 में क्या हुआ सस्ता और महंगा?

- सस्ता - इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, साइकिल, लिथियम बैटरी, हीरे के आभूषण।
- महंगा:- सोना, आयातित चाँदी, प्लेटिनम, विदेशी किचन चिमनी, सिगरेट।

Note:- 2023-24 का बजट अमृत काल में पहला बजट है।

- बजट: व्यय, कर, लेन- देन और योजनाओं का ब्लूप्रिंट है।
- संविधान के अनुच्छेद- 112 में बजट शब्द का उपयोग न करते हुए इसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है।
- यह बजट आगामी वर्ष 2023- 24 के लिए पेश किया गया है।
- वर्ष 2022- 23 में भारत की विकास दर 7% के आस-पास रही है, जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसी महामारी कोविड-19 और वैश्विक मंदी जो रही है।
- वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा गया था। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रही है।
- वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9 प्रतिशत रखा गया है और इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है ।
- वर्ष 2023-24 का बजट 7 मूल आधारों पर आधारित है, जिसे सप्त ऋषि- 7 कहा गया है।

1. समावेशी विकास - (a)कृषि (b)स्वास्थ्य क्षेत्र (c)शिक्षा क्षेत्र
2. वित्तीय क्षेत्र
3. युवा शक्ति
4. आखिरी व्यक्ति तक पहुंच
5. अवसंरचना निवेश
6. सक्षमता का विकास
7. हरित विकास

कृषि और सहकारिता:- ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि

- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम
- भारत को श्री अन्न देने के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

- पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य।
- भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग।
- भारत मिलेट (बाजरा) को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है।

❖ **स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि:-** वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत।

- वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए उन्मूलन मिशन की शुरुआत।
- चुने हुए ICMR लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सीय अनुसंधान को प्रोत्साहन।
- फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत।

❖ **आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना :** "कोई पीछे न छूटे"

- प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत।
- कर्नाटक के सूखा संभाव्य क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता।
- 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 से अधिक शिक्षकों की भर्ती।
- PMGKAY के तहत, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
- प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए 'भारत श्री' योजना की शुरुआत।
- पीएम- आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि।

अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश :-

विकास व रोजगार के अवसरों में वृद्धि:

- पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया।
- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, अवसंरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हित धारकों की सहायता करेगा।
- UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी- 2 और श्रेणी- 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन।
- राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा।

Note- अमृत काल के लिए संकल्पना: "सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था"

- इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

  1. नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।

  2. विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना।

  3. वृहद् आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना।

❖ अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं -

1. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:
2. पीएम- विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)
3. पर्यटन
4. हरित विकास

❖ **अध्यापकों का प्रशिक्षण:-** नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत् पेशेवर विकास, डिपास्तिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा।

- बच्चों और किशोरों के लिए "राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तका लय" की स्थापना की जाएगी।

❖ **अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना:** - सरकार द्वारा आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया गया है।

❖ **आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम:** - हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

❖ **एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल:-** अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा।

- **भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री) :-** 'भारत साझा पुरालेख निधान' एक डिजिटल

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

RAS MAINS गत वर्ष प्रश्न

प्रश्न-1. उन फसलों के नाम बताइये जिनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है ?

प्रश्न-2. राजस्थान में डेयरी विकास हेतु सरकार की योजना पर लघु लेख लिखिए ?

प्रश्न-3. गाय व भेड़ की 4+4 नस्लों के नाम लिखिए ?

प्रश्न-4. राज्य में कृषि का उत्पादन मानसून के पर्याप्त समयावधि में उचित व समान वितरण पर निर्भर है व्याख्या कीजिए ?

प्रश्न-5. राजस्थान में कृषि उत्पादकता की स्थिति तथा इस संबंध में राज्य में चल रही विभिन्न योजनाएँ बताइये ?

अध्याय – 2

ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना

ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद - राजीविका (RGAVP)

RGAVP एक स्वायत्त संस्था है जिसे अक्टूबर, 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था । यह समिति, समाज पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है और स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है।

वर्तमान में, RAJEEVIKA द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं लागू की जा रही हैं: -

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (RRLP) जून, 2011 से 60 विभागों में कार्यान्वित की जा रही है।
- अप्रैल, 2013 से 9 विभागों में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) लागू की जा रही है।
- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को अप्रैल, 2013 के बाद से चरणबद्ध तरीके से शेष विभागों में लागू किया जा रहा है।

राजस्थान में क्षेत्रीय विकास योजनाएं

मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान

यह परियोजना वर्ष 2016-17 में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालौर जिलों में प्रत्येक में एक ब्लॉक में कार्यान्वित की जा रही है सिरोही (पिंडवाड़ा) और जोधपुर (बालेसर) के दो नए ब्लॉकों को योजना में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत, क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (SHG) का गठन किया गया है तथा इन्हे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक साख सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेव के निवास क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मेव समुदाय अलवर और भरतपुर जिले के 12 ब्लॉक में केंद्रित है। मेव अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिए, राजस्थान सरकार मेवात क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए 1987-88 से एक विशेष विकास कार्यक्रम चला रही है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

केंद्रीय प्रवर्तित योजना (CSS) के रूप में 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) पेश किया गया था। BADP केंद्रीय सरकार की नीतिगत पहल है । जिसके अनुसार सीमावर्ती जिलों का संतुलित विकास किया जाना है।

यह कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 ब्लाकों, में लागू किया जा रहा है। BADP के तहत, ज्यादातर फंड सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए निवेश किया जाता है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राजस्थान सरकार द्वारा 2004-05 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनः लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झलावाड़ , भरतपुर, कोटा और बूंदी) की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतें शामिल हैं ।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान का दक्षिणी मध्यवर्ती हिस्सा विशेष रूप से अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद की पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह हिस्सा जनजातीय क्षेत्र विकास (TAD) के तहत कवर नहीं किया जाता तथा स्थानीय रूप से "मगरा" नाम से जाना जाता है।

निवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए, 5 जिलों के 14 ब्लॉकों में 2005-06 से "मगरा क्षेत्र विकास अभियान" शुरू किया गया था। वर्तमान में यह उपरोक्त जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए जल विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की गतिविधियां संचालित की गई हैं।

गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना (GGJVY)

राज्य के सभी 33 जिलों में गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना 30.09.2014 को शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास, रोजगार सृजन, निर्माण और सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव के लिए सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है । यह योजना राज्य द्वारा वित्त पोषित है और राज्य के ग्रामीण इलाकों में कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत "शमशान/कब्रिस्तान" की सीमा-दीवारों के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जाएगा । अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, 70 प्रतिशत धनराशि और जनजातीय उप योजना (TSP) क्षेत्रों में 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

विधान सभा के सदस्यो द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)

इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता की मूलभूत संरचना बनाने और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए स्थानीय जरूरत आधारित आधारभूत संरचना का विकास करना है । यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 2.25 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए सालाना कुल आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत अनुशंसित होना चाहिए । मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना (MJSY) के तहत कुल आवंटन का 25 प्रतिशत या कुल कार्यों का 25 प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

RAS गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न :-

प्रश्न-1. राजस्थान में जैव ईंधन ऊर्जा के स्त्रोत क्या है? (RAS - 2021)

प्रश्न-2. राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास के लिए क्या रियायतें और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ? (RAS - 2012)

प्रश्न-3. राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की दृष्टि एवं प्रमुख उद्देश्यों को समझाइये? (2021)

प्रश्न-4. राजस्थान में स्थापित 'पार्टनरशिप ब्यूरो' के क्या उद्देश्य हैं? (RAS - 2018)

प्रश्न-5. राजस्थान में औद्योगिक विकास को समझाइये ?

अध्याय – 5

प्रमुख विकास एवं आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं

आर्थिक संवृद्धि (Economic growth) - आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय निश्चित समय अवधि में किसी **अर्थव्यवस्था में** होने वाली **वास्तविक आय में वृद्धि** से है।

- सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा **प्रति व्यक्ति आय** में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि **आर्थिक समृद्धि** हो रही है।
- 70 के दशक में आर्थिक समृद्धि को तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन अब इसमें अंतर किया जाता है।
- अब आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखी जाती है साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक **घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद** तथा **प्रति व्यक्ति आय** को हम सामान्यतः **आर्थिक समृद्धि की आय** के रूप में स्वीकार करते हैं।

आर्थिक विकास (Economic Development)

- आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसके परिणाम स्वरुप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है।
- इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है अर्थात् इस में आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है।
- आर्थिक चरणों में उपरोक्त वर्णित शामिल होते हैं तथा गैर आर्थिक आर्थिक चरों के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्त्रोतों के गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं।
- इस प्रकार आर्थिक संवृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक।
- पहले का संबंध राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से जुड़ा है, जबकि दूसरे का संबंध राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अलावा अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन से होता है।

- अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना या प्रक्रिया है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगातार गिरता जाता है।
- जबकि उद्योगों, सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग व निर्माण गतिविधियों का स्तर बढ़ता जाता है इस प्रक्रिया के दौरान श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे में भी परिवर्तन होता है और उसकी दक्षता एवं उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

आर्थिक संवृद्धि बनाम आर्थिक विकास (Economic growth versus economic development)

- **आर्थिक समृद्धि** और **आर्थिक विकास समान प्रतीत** होने वाली अवधारणाएं है, परंतु तकनीकी दृष्टि से दोनों समान नहीं है, आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है -

1. **सकल घरेलू उत्पाद** में एक निश्चित **अवधि में वास्तविक वृद्धि।**
2. एक निश्चित अवधि में **प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद** में **वृद्धि।**

- वास्तव में, **आर्थिक समृद्धि** से आशय **सकल घरेलू उत्पाद**, (GDP) **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** एवं **प्रति व्यक्ति आय** में निरंतर होने वाली **वृद्धि** से है। अर्थात् आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है।
- आर्थिक समृद्धि में देखा जाता है कि **राष्ट्रीय उत्पादन** में सतत् **वृद्धि** हो रही है अथवा नहीं यदि **राष्ट्रीय उत्पादन में लगातार वृद्धि** हो रही है, तो इसे **संवृद्धि** की संज्ञा दी जाएगी।
- आर्थिक संवृद्धि से पता चलता है, कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्त्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है।

  आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण से है, इसमें गरीबी बेरोजगारी तथा असमानता के में कमी आती है, आर्थिक संवृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है।

आर्थिक विकास दर (Economic growth rate)

- **सकल घरेलू उत्पादन** में परिवर्तन की दर **आर्थिक विकास दर** कहलाती है

  आर्थिक विकास दर = गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन (वृद्धि या कमी)

आर्थिक संवृद्धि दर (Economic growth rate)

- **निबल राष्ट्रीय उत्पाद** में परिवर्तन की दर **'आर्थिक संवृद्धि दर'** कहलाती है इसको **राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर** भी कहा जाता है।

  आर्थिक संवृद्धि दर = गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के एनएनपी में परिवर्तन वृद्धि या कमी / गत वर्ष का एनएनपी X 100

  भारत जैसे विकासशील देशों में **आर्थिक संवृद्धि दर**, आर्थिक विकास दर की तुलना में कम होती है।

आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Economic Growth)

आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है -

आर्थिक घटक

- प्राकृतिक संसाधन
- पूँजी उत्पादन अनुपात
- संगठन
- श्रम शक्ति एवं जनसंख्या
- तकनीकी प्रगति
- वित्तीय स्थिरता
- पूँजी निर्माण
- आधारभूत संरचना
- विकासात्मक नियोजन

गैर आर्थिक घटक

- सामाजिक घटक
- राजनीतिक घटक
- धार्मिक घटक

आर्थिक विकास की माप

विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए पाँच दृष्टिकोण हैं-;

(A) आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम - (Basic Needs Approaches) इस दृष्टिकोण का प्रतिवादन-1970 में **विश्व बैंक** ने किया।

(B) जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक (Physical Quality of Life Indext - PQLI) इस इंडेक्स को **जॉन टिनवर्जन** एवं **मारिश डी० मारिश** ने प्रस्तुत किया।

अन्तर्गत आर्थिक विकास के मापन के लिए तीन सूचकांक का प्रयोग किया जाता है।

1. **जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)**
1. बाल मृत्युदर (Infant Mortality)
2. साक्षरता (Literary)

(C) निबल आर्थिक कल्याण (Net Economic Welfare) मापक - विलियम नोरधस तथा जेम्स टोबिन ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जो आर्थिक विकास की मापक है, की माप के लिए मंजर ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर (MEW) की धारणा विकसित की जिसे बाद में सेमुएलसन और संशोधित किया तथा इसे (NEW) मापक रहा।

NEW =G.N.P (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)-(उत्पादन भप्रत्यक्ष लागत तथा आधुनिक नागरिक की हानियाँ तथा गृहणियों की सीमाएँ ।

(D) क्रय शक्ति समता विधि (Purchasing Power Parity Method):- इस विधि का प्रतिपादन जी०आर० कैसेल ने किया। इसके अन्तर्गत किसी देश की **सकल राष्ट्रीय आय** के किसी पूर्व निश्चित **अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर** पर व्यक्त न करें, उस **देश के भीतर मुद्रा** की **क्रय शक्ति** के आधार पर व्यक्त किया जाता है। वर्तमान के **विश्व बैंक** इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन-सहन की तुलना के लिए कर रहा है।

(E) मानव विकास सूचकांक (Human Ebullient India):- इस सूचकांक की अवधारणा यूनाइटेड नेशन्स प्रोग्राम से जुड़े प्रसिद्ध **अर्थशास्त्री महबूत उल हक एवं उनके अन्य सहयोगी ए० के० सेन तथा सिंगर हंस** ने **1990** में किया।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

RAS MAINS गत वर्ष प्रश्न

प्रश्न-1. आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए ?
प्रश्न-2. आर्थिक विकास समृद्धि की अवधारणा बताइये?
प्रश्न-3. राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक समृद्धि को समझाइये ?

❖ प्रमुख विकास परियोजनाएं

1. **मुख्यमंत्री निः शुल्क निरोगी राजस्थान योजना :-**

- शुभारम्भ : 1 मई 2022
- "मुख्यमंत्री निः शुल्क दवा योजना" और "मुख्यमंत्री निः शुल्क जांच योजना" की सीमाओं का विस्तार करने के लिए 1 मई 2022 से शुरुआत।
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित

निरोगी राजस्थान अभियान :

शुरू 18 दिसम्बर 2019 14 और उनके वितरण 15 या योजना के तहत मौसमी बंचारी रोग, मक रोग, प्रदूषण आदि पर नियंत्र 2. चिकित्सालय द्वारा संचालित

(3) युद्ध के लिए युद्ध अभिमान :-

शुरू 26 अक्टूबर 2020

उद्देश्य : राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए। एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी खाद्य-सुरक्षा अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित ।

(4) मुख्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना :-

शुरू 1 मई 2021

यह योजना चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित ।

बजट 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किया गया ।

योजनान्तर्गत हॉस्पिटल में भर्ती के 05 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है ।

योजना का उद्देश्य :

(1) पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना ।
(2) पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों के

अध्याय – 7

राजस्थान आर्थिक समीक्षा एवं बजट

अध्याय – 1

वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य

➤ **GSDP (Gross state domestic product सकल राज्य घरेलू उत्पाद)** – एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को GSDP कहते है ।

GSDP – (प्रचलित कीमत पर) 2022-23 वृद्धि दर

GSDP 1413620 16.04%

कुल (14.14 लाख) देश की (प्रचलित कीमतों पर) GSDP का % (5.18%)

स्थिर कीमतों पर – (2011-12) वृद्धि दर

देश की (5.7%) 799449 8.19%

GSDP हिस्सा

➤ **GSVA (Gross state value added सकल राज्य मूल्य वर्धन)** 2022-23 में (13.11लाख करोड़)

क्षेत्रवार	(प्रचलित कीमतों पर) वृद्धि 2022-23= 13.11 लाख (15.57%) वृद्धि	स्थिर कीमतों पर वृद्धि 1.33 लाख – 7.88% वृद्धि
कृषि	28.95%	28.50 %
उद्योग	27.31%	27.76%
सेवा	43.74%	43.74%

➤ **NSDP (Net state domestic product शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)**- सकल घरेलू राज्य उत्पाद में से स्थाई पूँजीगत उपभोग घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है

स्थिर कीमतों पर मूल्यों (2011-12) 694771 (लाख करोड़) 16.10% की वृद्धि

प्रचलित कीमतों / मूल्यों पर 1259527 (लाख करोड़) 8.11% की वृद्धि

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है ।

➤ **CPI (Capital per Income) प्रति व्यक्ति आय** वृद्धि

स्थिर कीमतों पर (2011-12) 86134 6.94 %
प्रचलित कीमतों / मूल्यों पर 156149 14.85%

- **कुल खाद्यान्न उत्पादन – 253.99 लाख मैट्रिक टन**
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12 = 100) – 134.65**
- **थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-20) = 388.29**
- **अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा नवंबर 2022 तक) = 23487 मेगावाट (MW)**
- **वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर 2022) = 441569 करोड़**

➤ **CPI – Consumer per Index (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)** – द्वारा 4 सूचकांक जारी किए जाते है ।

1. औद्योगिक श्रमिकों (CPI- IW (Industrial Workers) के लिए (आधार वर्ष 2016)
2. कृषि श्रमिकों (CPI – AL (Agriculture labours के लिए (आधार वर्ष 1986-87)
3. ग्रामीणों श्रमिकों (CPI- Rural labours)

नोट :- उपयुक्त तीनों प्रकार के सूचकांक श्रम ब्यूरों, शिमला द्वारा जारी किए जाते है ।

4. ग्रामीण और शहरी (CPI- Rural and Urban) के लिए (आधार वर्ष 2012)

यह सूचकांक NSO, नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है ।

WPI (थोक मूल्य सूचकांक) (आधार वर्ष 1999 – 2000)

इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है ।

(75- प्राथमिक, 69 विनिर्मित उत्पाद, 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में सम्मिलित

अध्याय – 2

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित है।

राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा 594.20 mm दर्ज की गई जो सामान्य वर्षा 430.80 mm से 37.93 % अधिक है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में (GSVA) सकल राज्य मूल्यवर्धन)

	2011-12	2022-23
स्थिर मूल्यों पर	1.19 लाख	2.09 ब्याज करोड़
प्रचलित मूल्यों पर	1.19 लाख	3.39 लाख

वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन = 253.99 लाख मैट्रिक टन जो पिछले वर्ष (2021-22) में 231.52 से बढ़कर 9.71 % की वृद्धि

(GSVA) में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान

स्थिर मूल्यों पर (2011-12) = 28.56%, प्रचलित कीमतों पर = 28.95%

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी का योगदान

वर्ष 2022 – 23	क्षेत्र	योगदान %
3.79 लाख करोड़	1. फसल क्षेत्र	46.00%
	2. पशुधन क्षेत्र	46.41%
	3. वानिकी क्षेत्र	7.20%
	4. मत्स्य क्षेत्र	0.39%

नोटः- राजस्थान राज्य में पहली बार "समृद्ध किसान – खुशहाल राजस्थान के विचार के साथ पृथक् से कृषि "कृषि बजट 2022-23" (78,938.68) करोड़ प्रस्तुत किया गया।

कृषि बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान।

➢ भू – उपयोग –राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र - 2020-21 में 342.89 लाख हैक्टेयर है।

चित्रः 2.7

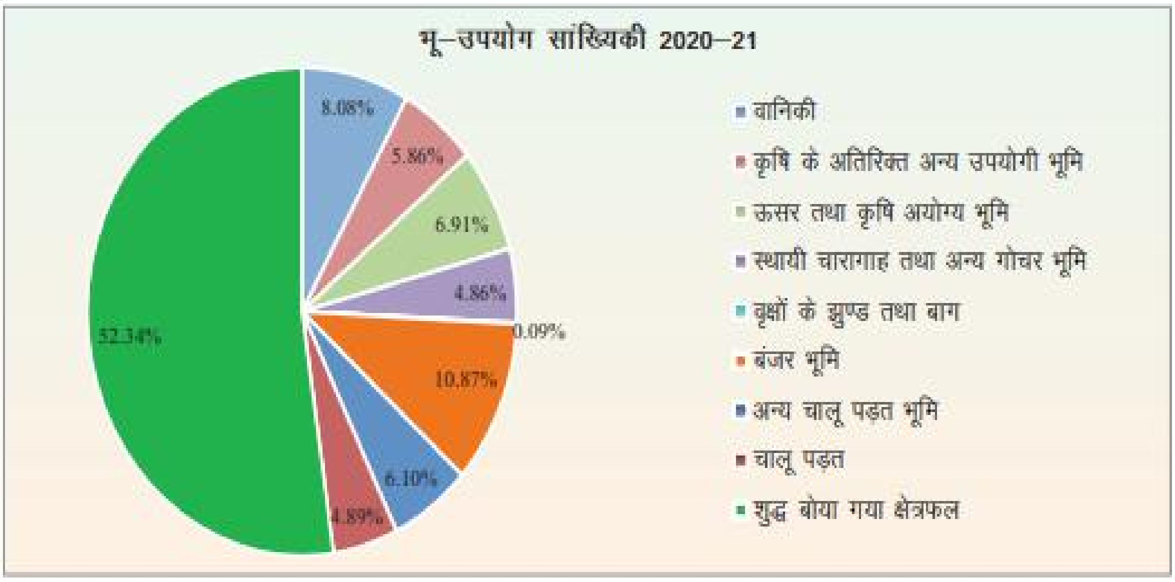

भाग - 1. शुद्ध बोये गए क्षेत्र .- 52.34%

2. बंजर भूमि = 10.87%

3. वानिकी = 8.08%

4. ऊसर एवं कृषि योग्य भूमि = 6.91%

5. अन्य चालू पड़त भूमि = 6.10 %

6. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि = 5.86 %

7. चालू पड़त भूमि = 4.89%

8. स्थाई चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि = 4.86%

- **प्रचलित जोत धारक :** राज्य में कृषि 2015 – 16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। जबकि 2010-11 में 68.88 लाख की थी जो अब 11.14% की वृद्धि दर्शाती है।
- कुल जोतों का सीमान्त 40.12%, लघु 21.90% अर्द्ध मध्यम 18.50% मध्यम 14.79% (यह तीनों में वृद्धि को दर्शाता है) एवं बड़े आकार 4.69% की वर्गीकृत जोत है। (बड़े आकार की जोतों में वृद्धि को दर्शाता है)

- **प्रचलित महिला जोत धारक** : राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। जो 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख हो गई। जो 41.94% की वृद्धि को दर्शाता है।

राज्य में वर्ष 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्र 13.30 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015 – 16 में बढ़कर 16.55 लाख हैक्टेयर हो गया अर्थात् वृद्धि 24.44% को दर्शाता है।

कृषि उत्पादन : राज्य में वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 253.99 लाख मैट्रिक टन जो गत वर्ष 2021 – 22 = 231.52 9.71 % वृद्धि।

वर्ष 2022-23 में खरीफ अनाज का उत्पादन = 77.84लाख मैट्रिक टन

गत वर्ष में खरीफ अनाज का उत्पादन = 72.74 7.01% वृद्धि

वर्ष 2022-23 में रबी अनाज का उत्पादन 128.73 लाख मैट्रिक टन गत वर्ष में रबी अनाज का उत्पादन = 1118.26 लाख मैट्रिक टन	+8.85% वृद्धि
2022-23 खरीफ दलहन का उत्पादन – 20.14 लाख मैट्रिक टन गत वर्ष (2021-22) खरीफ दलहन का उत्पादन- 27.44 लाख मैट्रिक टन	+53.98 % वृद्धि
2022-23 रबी दलहन का उत्पादन – 27.28 लाख मैट्रिक टन 2021-22 रबी दलहन का उत्पादन – 27.44 लाख मैट्रिक टन	+ 0.58% वृद्धि
तिलहन का उत्पादन वर्ष 2022-23 में – 99.78 लाख मैट्रिक टन तिलहन का उत्पादन वर्ष 2021-22 में – 102.68 लाख मैट्रिक टन	- 2.82 कमी
2022-23 खरीफ तिलहन का उत्पादन – 33.64 लाख मैट्रिक टन 2021-22 खरीफ तिलहन का उत्पादन – 28.92 लाख मैट्रिक टन	+ 16.32 % वृद्धि
2022-23 में रबी तिलहन का उत्पादन – 66.14 लाख मैट्रिक टन 2021-22 में रबी तिलहन का उत्पादन – 73.76 लाख मैट्रिक टन	- 10.33% कमी

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk8S6W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)

whatsa pp- 1 https://wa.link/9qwi7z web.- https://bit.ly/41wfqPD

FREE SAMPLE

RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/9qwi7z

Online order - https://bit.ly/41wfqPD

Call करें - 9887809083